

Regarding monitoring of utilization of funds allocated under DMFT to States-laid

श्री संजय सेठ (राँची): District Mineral Foundation Trust (DMFT) एक ऐसी निधि है जिसके तहत भारत सरकार राज्यों को खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास और नागरिकों के जीवन में सुधार, स्वरोजगार जैसे कल्याणकारी कार्यों के लिए बड़ी राशि उपलब्ध कराती है। झारखंड का दुर्भाग्य है कि बड़ी राशि की उपलब्धता के बावजूद जिला प्रशासन और राज्य सरकार के पास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कोई ठोस प्लान नहीं है। इस कारण जिला प्रशासन के पास पैसे पड़े हुए हैं और खनन प्रभावित क्षेत्र के लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। मेरे रांची में डी0 एम 0 एफ 0 टी0 के तहत 155 करोड़ रुपए मिले परंतु इसमें सिर्फ 70 करोड़ रुपए के आसपास ही सरकार और जिला प्रशासन खर्च कर पाए हैं। जबकि रांची में खनन प्रभावित क्षेत्र के लोग आज भी पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार के द्वारा दिए जा रहे पैसे पर भारत सरकार का कोई अधिकार नहीं रहता। वर्तमान समय में सांसदों को भी समिति से बाहर कर दिया गया है। मेरा सुझाव है कि इस विषय में संशोधन किया जाए। भारत सरकार का हस्तक्षेप डी0 एम 0 एफ 0 टी0 के क्रियान्वयन में हो ताकि खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, क्षेत्र का समुचित विकास हो सके।